The dues have accumulated over a period of time because of wide gap between' the value of coal supplied by coal companies, and payments made by the power utilities.

(d) One of the main reasons for non-ctearanee of coal bills is the financial constraints faced by the power utilities. Following are the important steps taken to recover the outstanding dues :

(i) All power units commissioned after 1-4-89 were being supplied coal only against advance payments or against revolving Letter of Credit.

(ii) Government of India have decided to adjust all undisputed coal sales outstanding as on 31-5-1990 against the Central Assistance to State Plans payable to the State Governments whose State Electricity Boards and Power Utilities had defaulted, in four equal instalments.

(iii) As a result of mounting arrears of outstanding dues, Ministry of Coal advised CIL to start supplying coal to the Power Utilities only against advance payments. This scheme which is better known as Cash and Carry Scheme was introduced with effect from 1-10-1991.

(iv) State Government have been requested to pursuade/enable their State Electricity Boards to clear the outstanding dues at the ear-list.

मंत्रालय के साथ सांसदों का पत्र-व्यवहार

286. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के दौरान सांसदों द्वारा मंत्रालय को कितने पत्र लिखे गए और उनका क्रमवार वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने पत्रों की पावती भेजी गई ;

(ग) कितने पत्रों के अन्तिम उत्तर भेजे गए; और

(घ) मंत्रालय द्वारा भेजे गए क्रमशः सकारात्मक और नकारात्मक उत्तर वाले अंतिम पत्रों के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मेघालय को रॉयल्टी के रूप में दी गई धनराशि

287. **श्री शिव चरण सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कोयले के कुल कितने भंडार हैं और कोयले की वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा देश में इसका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) देश में कोयले के उत्पादन तथा इसकी आवश्यकता के बीच कितना अंतर है और विदेशों से आयातित कोयले की मात्रा तथा उसकी दर का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेघालय को रॉयल्टी के रूप में कोई धनराशि दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रायल्टी की धनराशि कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) (क) और (ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए